



## सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी

□ डॉ ममता मणि त्रिपाठी

संयुक्त राष्ट्र में सुधार वि व भर के नीति निर्माताओं के सम्मुख सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है समकालीन एक ध्रुवीय वि व में संयुक्त राष्ट्र से अधिक प्रभावी और समकक्ष भूमिका निभाने की आगी की जाती है। इसके 6 प्रधान अंगों में जनता का सबसे अधिक ध्यान सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली पर टिका है क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय भाँति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रमुख जिम्मा सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार एवं सुधार का मसला लंबे समय से उठाया जा रहा है पर पहली बार इस माँग को औपचारिक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र में 14 सितम्बर 2015 को स्वीकार किया, भारत के लिए यह कूटनीतिक उपलब्धि है। भारत लम्बे समय से सुरक्षा परिषद का पुर्नगठन और इससे अपनी स्थायी सदस्यता के दावे के लिए अभियान चलाता रहा है। भारत की इस पहल का असर यह हुआ कि भारत की दावेदारी का समर्थन करने वाले देरों की संख्या बढ़ती गयी। ब्रिटेन, रुस, अमेरिका जैसे देरों भारत के पक्षधर हैं। प्रस्तुत भोध पत्र में सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी तथा भारत के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर प्रकार भाला जायेगा।

भारत ने संपूर्ण वि व में मजबूत अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास, अभूतपूर्व वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति द्वारा वि व के मंच पर अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनायी है वहीं लोकतांत्रिक सदगुणों द्वारा भी वि व रंगमंच पर उपर्थिति दर्ज करायी है। इसके बावजूद बार-बार सुरक्षा परिषद में दावेदारी प्रस्तुत करने के उपरान्त सुरक्षा परिषद में अभी तक स्थान न मिलना चिंतनीय विषय है। दक्षिण एशिया में नयी महाक्षेत्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला भारत यदि सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। गुटनिरपेक्षा आंदोलन का प्राथमिक सदस्य तथा विकास गील देरों में अपना प्रमुख वर्चस्व रखने वाला भारत सभी तरह से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का पात्र है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर चर्चा लंबे समय से चली आ रही है पर पहली बार इस माँग को औपचारिक विचार-विमर्श के लिए 14 सितम्बर 2015 को स्वीकार किया गया है। 14

सितम्बर 2015 को भारत की पहल पर आम सभा ने अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये विषय के आधार पर आगे की चर्चा करने पर सहमति से निर्णय लिया और यह भारत की बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस प्रस्ताव का चीन विरोध कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिस मसविदे को मंजूरी दी वह सुरक्षा परिषद के पुर्नगठन की जरूरत को रेखांकित करता है। इस संस्था की तस्वीर में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहा है मसलन औपनिवेशिक दासता की विदाई का प्रक्रम बढ़ने के साथ-साथ इसके सदस्य देरों की संख्या भी बढ़ती गयी।

संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे निर्णायक निकाय सुरक्षा परिषद है जिसमें स्थायी सदस्य हैं—अमेरिका, रुस, ब्रिटेन, चीन एवं फ्रांस। इन राष्ट्रों को वीटों का अधिकार प्राप्त है। यानि इन्हें किसी प्रस्ताव को खारिज एवं स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद के पुर्नगठन और इसमें स्थायी सदस्यता के लिए अभियान चलाता रहा है। भारत की इस पहल का असर हुआ कि भारत की दावेदारी का समर्थन करने

वाले दे । की संख्या बढ़ी है। वीटों के अधिकार प्राप्त दे गों में ब्रिटेन तथा फ्रांस के अलावा अमेरिका भी भारत का समर्थन दोहरा चुका है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की माँग अतीत से उठती रही है पर पहली बार इस माँग को औपचारिक विचार-विम १ के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मत से मंजूर किया। वर्तमान समय में वैशिक संघर्षों तथा संकटों को देखते हुए आज ऐसा किया जाना पहले से कही अधिक जरुरी हो गया है। एक वर्ष के विचार-विम १ के बाद यदि सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो भारत सहित कुछ अन्य दे गों को परिषद की स्थायी सदस्यता मिल सकती है। वीटो पावर माँग स्थायी दे गों के पास ही सुरक्षित है यहाँ तक कि इन्हे महासभा द्वारा बहुमत को भी निरस्त करने का अधिकार है। यही वह एकाधिकार है जो P-5 दे गों की भावित में विभाजन नहीं दे रहा है। दूसरे वि व युद्ध के उपरांत भााांतिप्रिय दे गों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था इसका मुख्य उद्दे य भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से सुरक्षित रखना था हालौंकि सुरक्षा परिषद को इसमें सफलता नहीं मिली। इजरायल और फिलीस्तीन के बीच अनवरत युद्ध भारत का तीनबार पाकिस्तान के साथ और एक बार चीन के साथ युद्ध हो चुका है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा हुआ चीन किसी वैि वक संस्था के आदे । को नहीं मानता है इसलिए आज आव यक है कि सुरक्षा परिषद के वर्तमान स्वरूप में बदलाव किया जाय। 1945 में परिषद के अस्तित्व में आने से लेकर अब दुनिया बड़े परिवर्तनों की वाहक बन गयी है। नई आर्थिक भावितायाँ, भावित के नये केन्द्रों के रूप में वि व मंच पर उभर रही हैं एक तरफ चीन मनमानी की तरफ अग्रसर है।

प्रन यह उपस्थित होता है कि भारत

है? इसका तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व भी सुरक्षा परिषद पर आधारित है इसके सभी कार्यक्रम तब तक कार्यरूप नहीं ले सकता जब तक उस पर सुरक्षा परिषद अपनी मुहर न लगा दे। यहाँ तक की सुरक्षा परिषद के अधीन ही संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसकी स्वीकृति के बिना बजट की आपूर्ति नहीं हो सकती है। भारत वि व का वि गालतम संगठन है जो वि व के बिखरे ध्रुवों को जोड़ने का कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ तब तक पंगु है जब तक सुरक्षा परिषद उनके कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान नहीं करती है ऐसी संस्था में कुछ गिने-चुने लोगों का एकाधिकार हो यह न तो औचित्य है, न वि व हित में है। भारत का भी कथन है कि सुरक्षा परिषद का पुर्नगठन होना चाहिए। वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने राष्ट्र संघ को एक नया कलेवर देने के लिए प्रयास किया जिसने 95 पृष्ठों की एक रिपोर्ट दी। सुरक्षापरिषद का यदि विस्तार होता है तो उसमें भारत की दावेदारी बनती है। सुरक्षा परिषद का विस्तार जरुरी है क्योंकि जिस समय यह संस्था अस्तित्व में आयी तब इसके 50 सदस्य थे और अब यह संख्या 193 हो चुकी है। भारत इसका सदस्य बनने हेतु कितना योग्य है इन आधारों पर देखा जा सकता है:-

1. भारत आबादी के दृष्टिकोण से दुनिया का दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवाँ बड़ा दे । है। यहाँ वि व जनसंख्या का 16 प्रति तत भाग निवास करता है।
2. भारत न सिर्फ दक्षिणी एि त्या की बड़ी भावित के रूप में उभरा है वरन् विकास ग्रील दे गों में भारत का अग्रणी स्थान है। तीसरी दुनिया के राष्ट्र भारत को अपने सच्चे हितैशी और प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं।
3. भारत गुटनिरपेक्षावाद दे गों का प्रमुख प्रवर्तक रहा है एवं वि व में भााांति निर्माण में इसकी

सक्रिय भूमिका रही है। कांगो, सोमालिया, सियरालोन, अंगोला, पूर्वी तिमोर, निकारागुआ, खाड़ी इत्यादि दे गों में भाँति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों ने

सराहनीय कार्य किए हैं तथा स्थानीय समुदाय के लिए चिकित्सा, प्राथमिक फैश्या, पेयजल, सड़क निर्माण इत्यादि की सुविधाएँ जुटाकर अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध पर भाँति रक्षक सैनिक भेजने में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

4. 120 दे गों के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के संगठन में किसी भी सदस्य को स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अतः सुरक्षा परिषद में इस बड़े भाग को प्रतिनिधित्व देनें के लिए भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए।

5. भारत भाँति तथा सह अस्तित्व पर आधारित वि व कल्याण की कामना करने वाला दे । माना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का भुरुआती सदस्य रहा है एवं इसने वि व में भाँति बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

6. वैं वक आतंकवाद का समूल विना । करने के लिए भारत के पास बहुआयामी एवं ठोस रणनीतियाँ हैं जिनकी अब तक प्रायः उपेक्षा की जाती रही है।

7. वर्तमान में भारत का नाभिकीय भावित है एवं इसने No. First Use के अपने सिद्धान्त के तहत हिन्द महासागर को भाँति का क्षेत्र बनाने की प्रतिबद्धता द राई है।

8. भारत वि व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका मानवाधिकार का रिकार्ड अत्यधिक उत्तम रहा है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में निहित मूल्यों का किसी भी राष्ट्र से ज्यादा कठिबद्धता के साथ अनुसरण करता है।

9. अपनी क्रय क्षमता के अनुसार भारत वि व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अनेक मामलों में भारत वि व का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है वि व के औद्योगिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है।

का सामना करने की क्षमता रखते हैं। प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण कर हमनें समूचे वि व को अपनी सामरिक भावित का एहसास करवा दिया गया है नौसेना के क्षेत्र में भारत परमाणु क्लब में भासिल हो गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में मंगलयान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आर्थिक क्षेत्र में भारत का समूचे वि व में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2008–09 की मंदी के दौर मेंअमेरिका जैसे दे । दिवालिया के स्थिति में आ गये वहाँ की तमाम कंपनियाँ और बैंक बंद हो गये, दे । में व्यापक बेरोजगारी बढ़ गयी कुछ दे । की विकास दर 2 से 3 प्रति तत रह गयी वहीं चीन के बाद भारत ही ऐसा दे । रहा जिसकी विकास दर 6.50 से 8.00 प्रति तत के बीच रही। भीत युद्ध के दौरान वि व में दो सैनिक गुट NATO एवं बार्सा गुट थे उस समय भारत के नेतृत्व में निर्गुट आंदोलन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण, निरस्त्रीकरण, वि व भाँति और सदस्य दे गों की आर्थिक समृद्धि से संबद्ध रहा था। मानवाधिकार के मामले में भारत की अलग रीति-नीति है। यहाँ महिलाओं, वृद्धों, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रयास किया गया है। भारत की दावेदारी को वि व के अनेक दे गों ने इसलिए भी समर्थन किया। इनमें न केवल ए । या, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोपीय दे । है बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन तो पहले से ही दावेदारी के समर्थक हैं, अब अमेरिका भी सहमत होते दिखायी दे रहा है।

**G.4 राष्ट्रों की माँग:** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के 4 दे गों के समूह G-4 के सरकार प्रमुखों की बैठक हुई। भारत के प्रधान मंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर अंगोला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री फैंजो एबे और ब्राजील के राष्ट्रपति डिलमा रसेल ने संयुक्त बयान में कहा कि ये चारों दे । परिवर्धित सुरक्षा परिषद के बैध प्रत्या गी हैं और एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं साथ ही उन्हाँनें चिंता जातायी कि 2005 के वि व फि अखर

सम्मेलन के बाद इस दि ॥ में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जिसमें सुरक्षा परिशद में भीघ्र सुधार का समर्थन किया गया है। इस सम्मेलन के बाद इन चार दे ॥ के प्रतिद्वन्द्वी दे ॥ ने अपने—अपने इलाकों में लामबंदी भुज़ दी है। चीन जापान को बर्दा त नहीं कर सकता है। इटली की जर्मनी से प्रतिस्पर्धा है। अर्जेण्टाइना और मैक्रिस्को ब्राजील के प्रतिद्वन्द्वी हैं। पाकिस्तान भारत के विरोध में खड़ा है, जिसे चीन का समर्थन है। हाल में बड़ा झटका यह रहा है कि द ॥ कों तक भारतीय दावे को चीन ने समर्थन दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ रोज पहले प्रस्ताव आया तो स्पष्ट रुख करने से वह मुकर गया। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सुरक्षा परिषद में विस्तार या सुधार आज भी उतना ही दूर है जितना एक द ॥ क पहले था जहाँ तक भारत का आर्थिक रुतवा बढ़ा है वहीं सुरक्षा एवं राजनीतिक मामलों में वह लगातार अदृ य होता गया। विकास लिल दे ॥ की प्रवक्ता की नैतिक हैसियत भी उसकी नहीं रही। उधर जर्मनी पाँच स्थायी दे ॥ के साथ P-5 के रूप में वै ॥ वक भूमिका निभा रहा है फिर G-4 अपने साथ किसी अफ्रीकी दे ॥ को तोड़ने में विफल रहा है। भारत अफ्रीका संपादक फोरम के उद्घाटन भाषण में सुषमा स्वराज ने कहा कि सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका और दुनिया की आबादी के छठे हिस्से वाले भारत को अब तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है।

भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उसे अपने आपको वै ॥ एक ताकतों के बीच स्थापित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत को एक कामयाबी हासिल हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने NOU में सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के लिए लिखित समझौता वार्ता का निर्णय लिया है। भारत संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावेदारों में दुनिया में अकेला दे ॥ नहीं है इसके अन्य प्रतिस्पर्धी दे ॥ हैं— जापान, जर्मनी, ब्राजील। वर्ष 2011–12 में पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के

समर्थन दिया था पर यह भी सत्य है कि यहीं दे ॥ भारत के लिए सबसे ज्यादा मुि कल बनेंगे। आर्थिक महा वित बनने के बावजूद भारत को अपने प्रतिस्पर्द्धी ताकतों जापान, जर्मनी और ब्राजील में प्रतिस्पर्द्ध करना होगा। अगर सकल घरेलू उत्पाद GDP की बात की जाय तो भारत का दुनिया में नौवा स्थान है जबकि जापान तीसरे और जर्मनी चौथे और ब्राजील सातवें स्थान पर है। अगर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट (2014) पर ध्यान दिया जाय तो यहाँ भी भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है जहाँ एक तरफ भारत 114 वें स्थान के साथ मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है जबकि जापान 66 तथा जर्मनी 17वें और ब्राजील 51वें उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र भावांति स्थापना में एक बड़े पैमाने पर अपनी भारीरिक उपरिथिति दर्ज करायी है लेकिन जब बात आर्थिक सहयोग की आती है तो पी-5 भारत से काफी आगे है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी तरह का सुधार किये बिना चार्टर में सं ॥ गोधन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो तिहाई दे ॥ द्वारा समर्थन जरुरी है यहीं नहीं इस संसोधन के बाद पी-5 दे ॥ दो के दो तिहाई सदस्य दे ॥ की संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा पुष्टि भी की जानी है यहाँ भी राह आसान नहीं है।

**संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समाधान के दो विकल्प हैं—**

1. तीन अस्थायी सदस्यों के साथ—साथ 6 नये स्थायी सदस्य भागील किये जाय।

2. सदस्यों की एक नयी श्रेणी बनायी जाए जिसमें एक अस्थायी सदस्य हो और आठ नये सदस्य भागील किये जायें, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का हो और उनका फिर से नवीनीकरण किया जाय। आज यह विषय जहाँ का तहाँ है, व्यौकि इसका विरोध पी-5 दे ॥ के साथ—साथ वे दे ॥ भी कर रहे हैं जो संबंधित महाद्विपों में जी-4 दे ॥ की प्रतिद्वन्द्वी की भूमिका में हैं। इसी विरोध का परिणाम है कि United For Consensus (UFC) अथवा कॉफी क्लब जिसका

पाकिस्तान सहित कई अन्य दे । करते हैं। यह मंच सुरक्षा परिषद में मौजूदा पाँच दे गो को ही स्थायी सदस्यता को सुरक्षित रखने का पक्षधर है।

एष्ट आया में पाकिस्तान चीन सहित कई दे । भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के रूप में देखना नहीं चाहते। यूरोप में जर्मनी को पूर्वी यूरोप के अधिकां । तथा पर्सी चम यूरोप के कुछ दे । देखना नहीं चाहते क्योंकि उनके मस्तिष्क पर जर्मन नाजीवाद का इतिहास तथा जर्मनी का वर्तमान वर्चस्ववाद नकारात्मक प्रभाव रखता है यहीं स्थिति चीन, रुस तथा कुछ दक्षिणी पूर्व एष्ट आयदे गों के बीच जापान तथा लातीन अमेरिकी दे गों सहित पर्सी चमी दुनिया के मध्य ब्राजील है इस मामले में दक्षिणी अफ्रीका का रास्ता अधिक सहज एवं सुरक्षित है, यहाँ Member State Africa Group dSjhdkWe vkSj Group 69 नें दक्षिणी अफ्रीका का सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए पूर्ण समर्थन किया है ऐसी स्थिति में जी-4 के प्रयासों की सफलता में बाधा नजरआ रही है तो क्या भारत द्वारा स्थायी सीट के वैयक्तिक प्रयास अधिक कारगर साबित हो सकता है।

आज संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य एवं आज्जर्बर सदस्य हैं, जबकि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या वही है जो 1963 में थी यानि 15 ही, इसका मतलब यह हुआ कि अब सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों का मात्र 7.77 प्रति ता है, जबकि वीटो धारक मात्र 2.59 प्रति ता। तात्पर्य यह है कि वैटो वक ताकरें दुनिया को और अधिक उदार व लोकतांत्रिक बनाने की वकालत करती रही लेकिन उन्होंने सुरक्षा परिषद के जरिए खुद को दुनिया का पुलिसमेन बनाए रखा परिणाम यह हुआ कि दुनिया संघर्ष, विखराव और आतंकवाद की तरफ खिसकती चली गई। इसलिए सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत जैसे दे । को स्थायी सदस्य बनाना आज की जरुरत है ।

म ह । स ॥ ॥

के रुच को देखकर वि वास होने लगा कि चीन और अमेरिका के अड़ंगे के बावजूद भी भारत की उम्मीद पूरी होगी। बहरहाल भारत और G-4 के अन्य दे गों के राजनीति की यह उपलब्धि सराहनीय है। भारत आज दुनिया की जरुरत बनता दिख रहा है फिर वह चाह श्रम का क्षेत्र हो, निवे । का क्षेत्र हो, भांति और सुरक्षा के मामले में भारत की सक्रियता का सवाल हो, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध व वैटो वक राजनीति में भारत की हैसियत, दुनिया इसे स्वीकार नहीं कर सकती ऐसे में यहीं प्रतीत होता है कि स्थायी सदस्यता का रास्ता भी बाजार होकर ही निकलेगा।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Khanna, V.N. the United nations new Delhi: R Chand and Company 2005
- Goldstein, Joshua, International Relation, New Delhi: Person Education Publication 2006
- Taylor, Paul and Groom, A.J. R.(eds) The United nations at the Millenium:
- Times of India (India has largest diaspora Population in the world, U.N. Report say, Jan 14, 2016, <http://timesofindia.indiatimes.com/news/other-news/>
- Indian Express 10 June 2016
- विस्वाल तपन, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-ओरियंट ब्लैकस्थान नई दिल्ली-2016
- राष्ट्रीय सहारा 19 सितम्बर 2015
- दैनिक जागरण 19 सितम्बर 2015
- परीक्षा मंथन :निबंध मंथन 2016-17

\*\*\*\*\*